हर जिले में होंगी 1000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, बाराबंकी में इंडो-डच सेंटर

लखनऊ में गामा रेडिएशन प्लांट तैयार जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा एक्सपोर्ट हब

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ : प्रदेश में खेती अब सिर्फ पेट भरने तक सीमित नहीं रह गई है। यह अब आमदनी, रोजगार और निर्यात का मजबूत जरिया बन रही है। प्रदेश में हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण की 1000 इकाइयां बनाने की योजना शुरू हो गई है। वहीं, फूलों और सब्जियों की उन्नत खेती के बारे में शोध और प्रशिक्षण के लिए बाराबंकी के त्रिवेदीगंज में इंडो-डच सेंटर फार एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।

यह सेंटर नीदरलैंड्स के सहयोग से बनाया जाएगा। इसका मकसद फलों-सब्जियों के उत्पादन को वैज्ञानिक आधार देना और निर्यात-योग्य बनाना है। इसके साथ ही सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के पास एक आधुनिक एक्सपोर्ट हब की योजना भी तैयार की है ताकि यूपी के उत्पाद यूरोप और अमेरिका के बाजारों तक पहुंच सकें। लखनऊ के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में गामा रेडिएशन प्लांट तैयार हो चुका है जहां फलों और सब्जियों को संक्रमण मुक्त किया जाएगा और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकेगी।

फलों और सब्जियों की खेती परंपरागत फसलों की तुलना में दो से ढाई गुणा ज्यादा मुनाफा देती है। साथ ही यह श्रम-प्रधान होने के कारण बड़े पैमाने पर रोजगार भी पैदा करती है।

संजीव पुरी, अध्यक्ष, सीआइआइ

बेरोजगारी में आई कमी किसानों की बढ़ी आमदनी

प्रदेश में अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर वैज्ञानिक, श्रम-प्रधान और मुनाफे वाली खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे प्रच्छन्न बेरोजगारी में कमी आई है और किसानों की आमदनी भी बढ़ी है।

17 हजार से ज्यादा यूनिट्स तैयार, महिलाओं को मिल रहा खास लाभ

प्रदेश में अब तक 17,000 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना के तहत यूनिट लगाने वालों को 35 प्रतिशत तक अनुदान और 30 लाख रुपये तक का कर्ज मिल रहा है। यदि इकाई किसी महिला के नाम पर है और वह सोलर प्लांट लगाना चाहती है, तो सरकार 90 प्रतिशत तक सब्सिडी देती है।

इन इकाइयों में नर्सरी, पौधरोपण, तोड़ाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और विपणन जैसे कई कामों में रोजगार मिलेगा। कोविड के बाद से लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिससे फल-सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ी है। एसबीआइ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति इनकी उपलब्धता सालाना सात से 12 किलोग्राम तक बढ़ी है। उत्पादन और खपत दोनों मामलों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है।